NTO 2.0 SET FOR A LEGAL HAUL

The TRAI regulation on NTO 2.0 is set for a long legal haul and battle in the courts. With the NTO 2.0 hearing postponed, TRAI assures no action till next hearing. The uncertainty regarding the implementation of NTO 2.0 prevails, as the broadcasters' petition against The Telecom Regulatory Authority of India's (TRAI) move to make them comply with the order by is being battled in the court.

The Bombay high court, suspended all the hearings due to heavy rains and is expected to hear it. TRAI directive citing a regulatory vacuum released a fresh directive on 24 July irking the broadcasters who have already been battling with the impact of the pandemic. TRAI had asked broadcasters to publish details including maximum retail price per month of channels and maximum retail price per month of bouquets of channels, the composition of bouquets and also amended reference interconnected offer (RIO) and other on their website.

Distribution platform operators (DPOs) have already complied with the network capacity fee (NCF), multi-TV charges, etc., under the new directive.

The legal tussle continues with the Bombay High Court now looking at deliver the judgement on NTO 2.0 on September 16. ■

TRAI Telecom Regulatory Authority of India

NTO 2.0

एनटीओ 2.0 के लिए कानूनी खींचतान

एनटीओ 2.0 पर ट्राई नियमन पर लंबी कानूनी खींचतान और अदालत में लड़ाई की तैयारी चल रही है। एनटीओ 2.0 की सुनवाई स्थगित होने के साथ ट्राई ने अगली सुनवाई होने तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया है। एनटीओ 2.0 के कार्यन्वयन को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गयी, क्योंकि भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के खिलाफ प्रसारणकर्ताओं की याचिका के अनुसार उन्हें आदेश का पालन करने के लिए अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है।

मुंबई उच्च न्यायालय ने भारी बारिश के कारण सभी सुनवाईयों को स्थगित कर दिया और उम्मीद की जाती है कि यह सुनवाई करेगा। ट्राई के निर्देश ने एक नियामक वैक्यूम का हवाला देते हुए 24 जुलाई को नया आदेश जारी किया, जो उन प्रसारकों को परेशान कर रहा था जो पहले से ही महामारी से जूझ रहे थे। ट्राई ने प्रसारकों को प्रति माह चैनलों की अधिकतम खुदरा मूल्य और चैनलों के बुके के अधिकतम खुदरा मूल्य, बुके की संरचना और उनकी वेबसाइट पर अन्य और रेफ्रेंस इंटरकनेक्शन ऑफर (आरआईओ) में संशोधन सहित विवरण प्रकाशित करने के लिए कहा था।

वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (डीपीओ) पहले ही नये निर्देश के तहत नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ), मल्टी टीवी शुल्क आदि का पालन कर चुके हैं।

अंतिम आदेश 16 सितंबर को सुनाया जायेगा। पीठ ने ट्राई को तब तक कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। ■

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

... You Know What You are doing But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW!

SATELLITE & Cable TV

- In-depth & Unbiased Market Information
- Technology Breakthroughs
- Comprehensive Circulation Across The Satellite & Cable TV Industry

Contact: Mob.: +91-7021850198 Email: scat.sales@nm-india.com